भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 806

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

तमिलनाडु में जल शक्ति अभियान की स्थिति

806. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल शक्ति अभियान (जेएसए) की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसके अंतर्गत इसके प्रारम्भ के बाद से तमिलनाडु में कवर किए गए जिलों और गांवों की संख्या का ब्यौरा शामिल है;

(ख) तमिलनाडु में आरणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त अभियान के तहत जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जलसंभर प्रबंधन में प्राप्त हुए प्रमुख परिणाम और सुधार क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली किन्हीं चुनौतियों या बाधाओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अभियान के तहत सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और संधारणीय जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है और केंद्र सरकार तकनीकी तथा आर्थिक सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। जल संरक्षण सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में देश के जल की कमी वाले 256 ज़िलों में समय-सीमा वाले, मिशन-मोड के रूप में जल संरक्षण अभियान के तौर पर 'जल शक्ति अभियान' (जेएसए) की शुरुआत की गई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में इस अभियान को 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) के रूप में शुरू किया, जिसका संदेश - "कैच द रेन: वेयर इट फाल्स, वेन इट फाल्स" था। तब से, जेएसए: सीटीआर एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है, जो स्थानीय स्तर पर कार्य और संस्थागत अभिसरण के माध्यम से जल सुरक्षा के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। जेएसए: सीटीआर अभियान को तमिलनाडु राज्य सहित देश के सभी ज़िलों (ग्रामीण और शहरी दोनों) में राष्ट्रव्यापी रूप में कार्यान्वित किया

गया और वर्ष 2023 से इसके प्रत्येक संस्करण में अधिक से अधिक प्रभाव डालने के लिए एक विशेष लक्ष्य पर ध्यान दिया गया है।

जनभागीदारी को और बढ़ाने के लिए, दिनांक 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत में "जल संचय जनभागीदारी" (जेएसजेबी) पहल की शुरुआत की गई। जून 2025 में जेएसजेबी 2.0 की शुरुआत की गई। जेएसजेबी 2.0 का कार्यान्वयन चक्र दिनांक 1 जून 2025 को शुरू हुआ और दिनांक 31 मई 2026 को समाप्त हुआ। दिनांक 1 जून 2026 को "जल संचय जनभागीदारी: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) - 2026 में शुरू किया गया, जिसने "जल संचय जनभागीदारी" (जेएसजेबी) पहल के दायरे को बढ़ाया और साथ ही इसे "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) अभियान के साथ जोड़ा।

जल शक्ति अभियान के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य सरकार ने जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के 4,47,997 संरचनाएं, पारंपरिक जल निकायों के जीर्णोद्धार के 44,494 कार्य, पुन: उपयोग और पुनर्भरण के 5,67,550 संरचनाएं और वाटरशेड विकास के 3,46,537 संरचनाएं बनाने की रिपोर्ट दी है। जिसमें अरनी लोकसभा क्षेत्र में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के 17,962 संरचनाएं, पारंपरिक जल निकायों के जीर्णोद्धार के 3,518 कार्य, पुन: उपयोग और पुनर्भरण के 24,490 संरचनाएं और वाटरशेड विकास के 12,324 संरचनाएं शामिल हैं। साथ ही, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया कि शुरुआत से ही सभी जिले और 12,480 पंचायतें जल शक्ति अभियान में शामिल हैं।

(ग): 'जल' के राज्य का विषय होने के कारण से जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं जैसे कि उनका संरक्षण का अध्ययन, योजना बनाना, धनराशि देना और उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य राज्य सरकारें स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के आधार पर करती हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा यह सूचित किया है कि उनके द्वारा जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि और शहरी निकायों जैसे विभिन्न संबंधित विभागों के मध्य आपसी समन्वय के माध्यम राज्य में 'जल शक्ति अभियान' को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

(घ): 'जल' के राज्य का विषय होने के कारण, लोगों में जागरूकता लाने सहित जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों का है। तथापि, भारत सरकार ने देश भर में कई पहलें शुरू कीं, जिनमें 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) भी शामिल है इसका उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के महत्व के संबंध में जागरूक करना और जल के प्रयोग के तरीकों में व्यवहार संबंधी बदलाव को बढ़ावा देना था। जागरूकता उत्पन्न करना जेएसए: सीटीआर अभियान के पाँच मुख्य हस्तक्षेपों में से एक है, जिसका उद्देश्य जल से संबंधित चुनौतियों और संरक्षण के महत्व के विषय में लोगों को जागरूक करना था, साथ ही इस बात पर बल देना था कि जल संरक्षण को एक जन-आंदोलन बनाया जाए।

जेएसए: सीटीआर के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सभी ज़िलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित करने का अनुरोध किया गया था। ये केंद्र संसाधन और ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं; ये जल से संबंधित मामलों पर जानकारी देते हैं, बेहतरीन तौर-तरीके प्रदर्शित करते हैं, तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं और जल संरक्षण की रणनीतियों के लिए स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। देश भर में 712 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु के 38 जेएसके भी शामिल हैं।

जेएसजेबी पहल समुदायों, सिविल सोसायटी और स्थानीय सरकारों को संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकार के नज़रिए से कम लागत वाले और स्थानीय स्तर पर उपयुक्त जल संरक्षण समाधान कार्यान्वित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पहल के अंतर्गत, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्लूएम) विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर, जल संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए, कई सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

अपनी पहुँच को और अधिक बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्लूएम) ने युवा मामले विभाग के साथ सहयोग से इसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और उसके युवा क्लबों के व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, ताकि 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण के प्रयासों में ज़मीनी स्तर पर जन भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

*****